Punishment for non-payment of Post Retirement Dues by M/s. Jessop

977. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:
SHRI NILOTPAL BASU:

Will the Minister of LABOUR be pleased to refer tothe reply to Unstarred Question 1016 given on 2nd December, 1996 and state:

(a) non-payment of gratuity, being a punishable offence as stated in the above reply, the agency/individual to be punished in the case of M/s. Jessop;

(b) whether Government's attention has been drawn to observation of BIFR Bench in this regard in the hearing of M/s. Jessop held on 26th February, 1996;

(c) whether Bench had stated that move of the Government to link gratuity payment to the
revival package did not flow from any direction
given by the Bench;

(d) whether the bench had expected Department of Heavy Industry to take a humanitarian view; and

(e) the time bound step taken by the Government to clear the dues in view of (c) and (d) above?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) The matter is being examined in consultation with concerned departments.

(b) to (d) Yes, Sir.

(e) The Department of Heavy Industry is taking appropriation action. It will be difficult to specify a time schedule.

देश में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार व्यक्ति

978. **प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1995, 1 जनवरी, 1996 और 1 जनवरी, 1997 तक रोजगार कार्यालयों में कितने बेरोजगारों के नाम दर्ज थे;

(ख) इन तीन वर्षों के दौरान इन कार्यालयों के माध्यम से कितने व्यक्तियों, महिलाओं व पुरुषों, को रोजगार मिला; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए क्या योजना बनाई गई है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) 31.12.1994, 31.12.1995 तथा 31.12.1996 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर, रोजगार चाहने वालों की संख्या, यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, क्रमशः 366.92, 367.42 तथा 274.30 लाख थी।

(ख) प्रत्येक वर्ष 1994-96 की अवधि के दौरान रोजगार कार्यालयों द्वारा नियोजितों की संख्या निम्नानुसार थी:-

(हजारो में)

वर्ष	नियोजितों की संख्या	
	परुष	महिलायें
1994	162.8	42.1
1995	171.3	43.6
1996	182.9	50.1

(ग) अल्प रोजगार की उच्च दर को मानते हुए निर्धनों के लिये रोजगार के अवसरों में वृद्धि की आवश्यकता है। इस संबंध में, नौवीं योजना में राष्ट्रीय रोजगार आश्वासन योजना कार्यान्वित करनी होगी।

नवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि एंव ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दिया जाना परिकल्पित है जिससे पर्याप्त उत्पादक रोजगार सृजन किया जा सके तथा गरीबी उन्मूलन किया जा सके। उत्पादक रोजगार राज्य की नीति का एक महत्पवपूर्ण पहलू है जिसमें समानता के साथ विकास प्राप्त करने का पर बल दिया गया है। उच्च बेरोजगारी तथा अल्प रोजगार दर वाले लक्ष्यों से युक्त क्षेत्रों में श्रम गहन क्षेत्रों, उप-क्षेत्रों तथा प्रौधोगिकियों पर ध्यान केन्द्रित होने से विकास प्रक्रिया में स्वतः ही उच्च उत्पादक रोजगार सृजित होगा।

Meeting of State Labour Ministers to implement the S.C. Order on Child Labour

979. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:
SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJI-RAO SHINDE:
SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether at a meeting of State Labour Ministers, Secretaries, Commissioners and the Planning Commission, ILO and the different State Government sought allocation of adequate